राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 246

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, बुधवार, 12 फरवरी 2020

www.jagran.com

पृष्ठ 16

दिल्लीवालों गजब कर दिया आपने, आइ लव यू। मैं सभी दिल्लीवासियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने तीसरी बार अपने बेटे पर भरोसा किया। हनुमान जी का मुझ पर आशीर्वाद है।
–अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री

फिर आप की हुई दिल्ली

आप की ताकत

- आप सरकार का शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए शानदार काम, मुफ्त बिजली-पानी, महिलाओं के लिए निशुल्क बस यात्रा
- चुनावी घोषणा पत्र में किए गए दावों पर भी मतदाताओं ने विश्वास जताया
- मुख्यमंत्री के रूप में केजरीवाल की लोकप्रियता जीत का बड़ा कारण
- चुनाव प्रचार में आक्रामक बयान से परहेज, सकारात्मक दावों पर जोर
- आरोप-प्रत्यारोप से दूरी, अपने किए काम को जनता तक पहुंचाना
- महिलाओं का भरोसा, एक्सिस माय इंडिया के एक्जिट पोल के मुताबिक 53 फीसद पुरुषों और 59 फीसद महिलाओं का आप को वोट देना

भाजपा की कमजोरी

- मुख्यमंत्री के चेहरे का न होना
- बड़े नेताओं की भीड़ और आक्रामक प्रचार के बीच स्थानीय मुद्दे पीछे छूटे
- केजरीवाल के खिलाफ नकारात्मक प्रचार पर जोर भी खिलाफ गया
- सीएए, एनआरसी के खिलाफ शाहीन बाग में प्रदर्शन का लंबा खिंचना
- कांग्रेस का अनमने ढंग से चुनाव लड़ने का भी आप को फायदा मिला

कांग्रेस की नाकामी

- शीला दीक्षित से आगे नहीं सोच पाना कांग्रेस पर भारी पड़ा
- पूरे चुनाव प्रचार के दौरान ठोस मुद्दों का अभाव नजर आया
- चुनाव प्रचार में बड़े नेता औपचारिकता पूरी करते दिखे। राहुल और प्रियंका आखिरी दो दिनों में सक्रिय हुए
- राहुल गांधी का पीएम मोदी पर दिया गया विवादित बयान भारी पड़ा
- पूरे चुनाव अभियान में स्थानीय से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक विफल रहा

नई दिल्ली विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद आप कार्यालय में लोगों का धन्यवाद करते (बाएं से) राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता ● ध्रुव कुमार

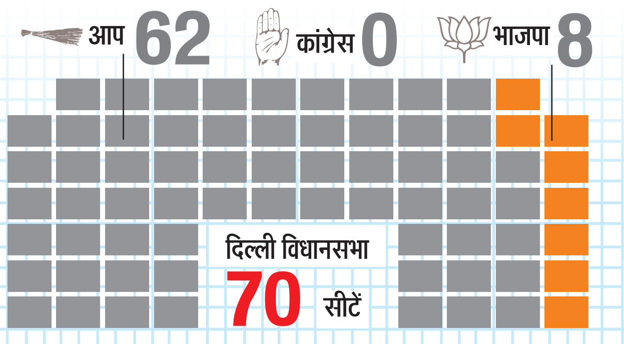

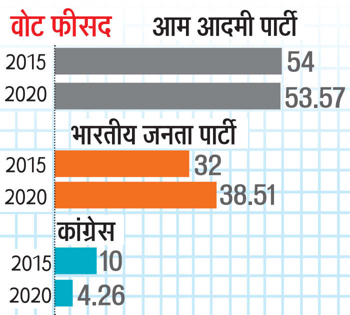

क्या कहते हैं वोट के आंकड़े

- आप ने सीटें भले ही सबसे ज्यादा जीतीं पर भाजपा को पिछली बार से 6.51 फीसद ज्यादा वोट मिले। भाजपा की 5 सीटें भी बढ़ीं।
- आप की सीटें घटीं। उसे मिले मतदान फीसद में मामूली कमी आई।
- आंकड़े बता रहे हैं कि द्विपक्षीय मुकाबले का फायदा आप को मिला
- कांग्रेस इस बार भी कोई सीट नहीं जीत सकी है। उसका वोट फीसद भी पिछली बार से 5.74 फीसद घट गया है।
- 2013 में कांग्रेस को 24.55 फीसद वोट व आठ सीटें मिली थीं। वहीं, आप को 29.49 फीसद वोट व 28 सीटें मिली थीं।

केजरीवाल की पत्नी को जन्मदिन का तोहफा

11 फरवरी को अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता का जन्मदिन भी था। भारतीय राजस्व सेवा (आइआरएस) की पूर्व अफसर रहीं सुनीता ने कहा कि वह अपने जन्मदिन पर इससे बेहतर तोहफे की उम्मीद नहीं कर सकती थीं जो दिल्ली की जनता ने उन्हें दिया है।

43108 वोट नोटा (कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं) को पड़े, जो कुल मतदान का 0.5 फीसद है।

46 मौजूदा विधायकों को चुनावी मैदान में उतारा था आप ने, इनमें से 44 ने जीत दर्ज की

प्रत्याशी	जीत का अंतर
अरविंद केजरीवाल	21,650
मनीष सिसोदिया	3,207
राघव चड्ढा	20,058
आतिशी	11,393
अमानतुल्लाह खां	71,823

आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को मेरी तरफ से जीत के लिए बधाई और शुभकामनाएं।
राहुल गांधी, कांग्रेस नेता

दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के लिए आप और अरविंद केजरीवाल को बधाई। दिल्ली के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उन्हें शुभकामनाएं।
नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

केजरीवाल तीसरी बार बनेंगे मुख्यमंत्री

- विस चुनाव में 70 में से 62 सीटें जीतीं
- 14 को रामलीला मैदान में शपथ संभव
- 17 आप विधायकों ने भी लगाई हैट्रिक

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली की जनता ने फिर अरविंद केजरीवाल पर विश्वास जताया है। सरकार के पांच साल में किए गए विकास कार्यों का जादू इस कदर चला कि आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए हुए चुनाव में 62 सीटें जीतकर जबर्दस्त सफलता का इतिहास दोहरा दिया। कांग्रेस इस बार भी खाता नहीं खोल सकी। भाजपा को वोट प्रतिशत में वृद्धि के साथ पांच सीटों का भी फायदा हुआ। उसे आठ सीटें मिली हैं। वहीं, केजरीवाल की अगुआई में आप दिल्ली में लगातार तीसरी बार जीतकर सरकार बनाएगी। शपथ ग्रहण कार्यक्रम शुक्रवार 14 फरवरी को रामलीला मैदान में हो सकता है, हालांकि इस बारे में अंतिम फैसला बुधवार को आप विधायक दल की बैठक में होगा।

दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल के बिजली, पानी, शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए कामों और महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा के फैसले को भरपूर समर्थन दिया है। यही वजह है कि आप अपना जनाधार बरकरार रखने में कामयाब रही।

लगातार दूसरी बार 60 से ज्यादा सीटें : पिछले विधानसभा चुनाव (2015) में आप ने 70 विधानसभा सीटों में से 67 सीटें जीतकर इतिहास रचा था। आप लगातार दूसरी बार दिल्ली में 60 से अधिक सीटें जीतकर सत्ता में आई है। दिल्ली में कांग्रेस के नेतृत्व में शीला दीक्षित की तीन बार सरकार रही थी, लेकिन कांग्रेस कभी 60 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई थी।

तीन लोस क्षेत्र में आप का क्लीन स्वीप: इस चुनाव में आप ने सात लोकसभा क्षेत्र में से तीन पश्चिमी दिल्ली, नई दिल्ली, चांदनी चौक की सभी 30 विधानसभा सीटें जीत ली हैं। पार्टी के सभी दिग्गज जीतने में सफल रहे हैं। इनमें केजरीवाल, गोपाल राय, सत्येंद्र जैन, इमरान हुसैन, कैलाश गहलोत, राजेंद्र पाल गौतम, विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल, उपाध्यक्ष राखी बिड़ला व सौरभ भारद्वाज शामिल हैं। भाजपा सांसद गौतम गंभीर के लोकसभा क्षेत्र पूर्वी दिल्ली व मनोज तिवारी के लोकसभा क्षेत्र उत्तर-पूर्व दिल्ली से पार्टी को तीन-तीन विधायक मिले। वहीं, दक्षिण दिल्ली, उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से एक-एक विधायक जीते हैं।

कांग्रेस के 63 उम्मीदवारों की जमानत जब्त

कांग्रेस के 66 में से 63 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। उसके उम्मीदवार किसी भी सीट पर दूसरे स्थान पर भी नहीं रहे। शीला सरकार में मंत्री रहे डॉ. एके वालिया, अरविंदर सिंह लवली, हारून यूसुफ, डॉ. नरेंद्र नाथ सहित कांग्रेस के सभी दिग्गजों को करारी हार का सामना करना पड़ा। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री आरपी सिंह भी चुनाव हार गए।

जनादेश (विशेष) पेज-4,5
दिल्ली का जनादेश (संपादकीय)

सरोकार

करेगा मधुमेह की जांच और बताएगा कि कितना इंसुलिन लें

धनबाद : आइआइटी के छात्रों ने सिर्फ दो हजार रुपये में ऐसा उपकरण तैयार किया है, जिसमें इंसुलिन पेन और ग्लूकोमीटर दोनों उपलब्ध हैं। यह शर्करा का स्तर तो बताएगा ही, यह भी तुरंत बताएगा कि कितना इंसुलिन लें। इस उपकरण का वजन महज 70 ग्राम है। यह बाजार में उपलब्ध उपकरणों से कहीं सस्ता व कारगर है। (पेज-11)

जागरण विशेष

अब स्टीव वॉ की किताब में छाएगा क्रिकेट का 'वंडर किड'

कोलकाता : अपनी अद्भुत बल्लेबाजी से सोशल मीडिया पर धूम मचाने वाला तीन साल का शेख शाहिद अब क्रिकेट बुक में छाने को तैयार है। यह किताब कोई और नहीं पूर्व क्रिकेटर स्टीव वॉ लिख रहे हैं, जो शाहिद से मिलने चुपचाप उसके घर पहुंचे। ऑस्टेलिया के दिग्गज खिलाड़ी ने शाहिद के साथ क्रिकेट खेला, तस्वीरें खिंचवाने के साथ ही भविष्य संवारने में मदद का भरोसा भी दिया। (पेज-11)

अर्थव्यवस्था में सुधार के लक्षण साफ दिखाई दे रहे : सीतारमण

- लोकसभा में वित्त मंत्री ने गिनाए सात 'ग्रीन शूट्स'

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अर्थव्यवस्था की दिशा और सुधार के संकेत को लेकर बार-बार सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों में सात 'ग्रीन शूट्स' (सुधार के अच्छे संकेत) गिनाए हैं। लोकसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने आंकड़ों के साथ यह भी साबित किया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में अर्थ प्रबंधन पूर्व की यूपीए सरकार से हर लिहाज में बेहतर है।

वित्त मंत्री ने आम बजट में उठाए गए 13 विभिन्न कदमों के जरिये यह भी दावा किया कि अर्थव्यवस्था के समक्ष जो भी चुनौतियां हैं उनके समाधान की सारी कोशिशें की गई हैं। अर्थव्यवस्था में सुधार के लक्षण गिनाते हुए उन्होंने कई तर्क रखे। सीतारमण ने वैश्विक स्तर पर भारत को लेकर बने सकारात्मक माहौल, पाइपलाइन में चल रही इन्फ्रा परियोजनाओं, औद्योगिक उत्पादन में सुधार, बढ़ते विदेशी मुद्रा भंडार को अच्छी आर्थिक सेहत का लक्षण बताया। जीएसटी संग्रह में सुधार व मैन्यूफैक्चरिंग इंडेक्स को भी वित्त मंत्री ने सुधार के लक्षणों में गिनाया।

कांग्रेस के काबिल डॉक्टरों ने अर्थव्यवस्था का किया गलत इलाज : निर्मला पेज>>12

ऐसे सुधर रही आर्थिक सेहत

- भारत को लेकर सकारात्मक वैश्विक माहौल। चालू वित्त वर्ष के पहले आठ माह में विदेशी निवेश 24.4 अरब डॉलर पर पहुंचा, जो पहले 21.4 अरब डॉलर था।
- 106 लाख करोड़ रुपये की इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं पाइपलाइन में। इनसे भी अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
- औद्योगिक उत्पादन में कई माह से जारी गिरावट थमी। नवंबर, 2019 में औद्योगिक उत्पादन दर 1.8 फीसद रही।
- मैन्यूफैक्चरिंग का पीएमआइ इंडेक्स भी सकारात्मक है। यह अर्थव्यवस्था में सुधार का संकेत है।
- विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 466.69 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है।
- जीएसटी संग्रह भी पिछले कुछ माह से यह एक लाख करोड़ रुपये के स्तर से ऊपर चल रहा है। जनवरी, 2020 में जीएसटी संग्रह 1.18 लाख करोड़ रुपये रहा था।
- प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में भी तेजी दिखने लगी है। आंकड़े अब इनमें सुधार की गवाही दे रहे हैं।

रिश्तों को मजबूती देने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप आएंगे भारत

- दो दिन की यात्रा पर 24 को पहुंचेंगे नई दिल्ली, अहमदाबाद भी जाएंगे
- दो अहम रक्षा सौदों समेत तीन बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर के आसार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा की तारीख तय हो गई है। ट्रंप 24 फरवरी को दिल्ली पहुंचेंगे। दो दिन के प्रवास के दौरान वह अहमदाबाद भी जाएंगे। उनकी यात्रा की घोषणा दोनों देशों की सरकार की तरफ से मंगलवार को अलग-अलग की गई। इस दौरान ट्रंप की पीएम नरेंद्र मोदी से चार से पांच दफे मुलाकात होगी। दोनों देशों के बीच कई समझौते हो सकते हैं, जिनमें दो अहम रक्षा सौदे भी शामिल हैं।

विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 'पीएम नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पत्नी मेलानिया के साथ 24-25 फरवरी, 2020 को भारत आएंगे। यह राष्ट्रपति की पहली आधिकारिक यात्रा होगी। ट्रंप दंपती दिल्ली और अहमदाबाद में भारतीय समाज के कई वर्गों से मिलेंगे। भारत-अमेरिका के बीच वैश्विक रणनीतिक साझेदारी सामान मूल्यों, आदर व आपसी सूझबूझ पर आधारित है। मोदी व ट्रंप की अगुवाई में दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत हुए हैं। कारोबार, रक्षा, ऊर्जा, आतंकरोधी अभियान, क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर दोनो देशों के बीच सहयोग काफी प्रगाढ़ हुए हैं। इस दौरे के दौरान दोनों नेताओं को रणनीतिक रिश्तों को और मजबूत बनाने का मौका मिलेगा।' उधर, वाशिंगटन में व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव स्टेफनी ग्रिशम ने कहा, 'पिछले सप्ताहांत मोदी-ट्रंप के बीच टेलीफोन पर बात हुई थी जिसमें भारत दौरे पर अंतिम सहमति बनी थी। यह यात्रा रणनीतिक रिश्तों को और प्रगाढ़ करेगी।' ट्रंप कार्यकाल के आखिरी साल में भारत आ रहे हैं। वैसे मोदी-ट्रंप की कई बार भेंट हो चुकी है। जून, 2017 में वाशिंगटन में मोदी पहली बार ट्रंप से मिले थे। मोदी ने उन्हें भारत यात्रा का न्योता दिया था। 2019 में उन्हें गणतंत्र दिवस पर बुलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन इच्छा के बावजूद ट्रंप नहीं आ सके थे।

डोनाल्ड ट्रंप फाइल फोटो

वर्ष 2000 के बाद हर अमेरिकी राष्ट्रपति ने की भारत की यात्रा पेज>>3

प्रोन्नति में कोटे के विवाद में सभी विकल्पों पर काम शुरू

- फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने और विधेयक जैसे कदमों पर सरकार कर रही मंथन
- कानूनी पहलुओं के अध्ययन के लिए भी लगाई टीम, कई राज्यों में इसे लेकर है विवाद

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पदोन्नति में आरक्षण पर उठे विवाद के बड़ा बवाल बनने से पहले ही केंद्र सरकार इसका रास्ता तलाशने में जुट गई है। उन सभी कानूनी पहलुओं पर विचार हो रहा है जो संभव हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने और संसद में इसे लेकर विधेयक लाने जैसे विकल्पों को भी प्रमुखता से रखा गया है।

सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को इससे जुड़े कानूनी पहलुओं को जुटाने के काम में लगाया है। साथ ही उन राज्यों से भी संपर्क करने को कहा है जहां पदोन्नति में आरक्षण को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। मौजूदा समय में उत्तराखंड ही नहीं, देश के कई राज्यों में पदोन्नति में आरक्षण को लेकर विवाद चल रहा है। इनमें मध्य प्रदेश, बिहार जैसे राज्य शामिल हैं। जिनके मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। इसके साथ ही कानूनविदों के साथ भी चर्चा शुरू कर दी गई है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को सक्रियता से लगाया गया है। जबकि पीएमओ के स्तर पर भी मंथन चल रहा है।

इससे पहले सरकार एससी-एसटी उत्पीड़न विरोधी कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से आए फैसले पर भी इसी तरह से एक विधेयक संसद में लाई थी। जिसके तहत उनके उत्पीड़न को रोकने के कानून के पुराने स्वरूप को बहाल कर दिया था।

सूत्रों के मुताबिक यदि विधेयक लाने का फैसला हुआ तो इसे बजट सत्र के दो मार्च से शुरू होने वाले अगले चरण में संसद में पेश किया जाएगा। एक मत पुनर्विचार याचिका का भी है, लेकिन वैसी स्थिति में मामला कोर्ट में रहते हुए विधेयक लाना थोड़ा असहज हो सकता है। पदोन्नति में आरक्षण का यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब उत्तराखंड के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि यह मौलिक अधिकार नहीं है। राज्य सरकारें इस पर अपने विवेक से फैसला कर सकती हैं।

बड़ा काम

उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में गर्बाधार से चीन सीमा लिपूलेख तक बन रही है 75 किलोमीटर लंबी सड़क, सामरिक दृष्टि से बेहद है इस सड़क का बनना

चीन सीमा अब चार किमी दूर, मालपा तक सड़क तैयार

- नेपाल-चीन सीमा पर तैनात जवानों को होगा फायदा
- कैलास मानसरोवर यात्रियों को होगा सीधा फायदा
- सीधे वाहन से चीन सीमा तक पहुंच सकेंगे

तेज सिंह गुंज्याल, पिथौरागढ़

उत्तर भारत को चीन से जोड़ने के लिए उत्तराखंड में बनाई जा रही गर्बाधार- लिपूलेख सड़क का काम मालपा तक पूर्ण हो गया है। अब मात्र चार किलोमीटर का काम बाकी है, जो इस वर्ष पूरा हो जाएगा। इसे नेपाल सीमा के समानांतर बनाया गया है। सड़क तैयार होने के बाद अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तैनात भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आइटीबीपी) और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) जवानों को काफी फायदा होगी। इसके साथ ही कैलास मानसरोवर यात्रियों की राह भी आसान हो जाएगी। श्रद्धालु सीधे वाहन से चीन सीमा तक पहुंच सकेंगे।

भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस सड़क के तैयार होने से जवानों का नेपाल एवं चीन सीमा क्षेत्र तक आवागमन आसान हो जाएगा। इतना ही नहीं, उन्हें सीमा तक आवश्यक सामाग्री पहुंचाने में भी मदद मिलेगी। अभी तक यह काम घोड़े और खच्चरों की मदद से किया जाता रहा। घोड़े और खच्चरों के माध्यम से धारचूला से अंतिम सीमा क्षेत्र तक पहुंचने में चार दिन का समय लगता है, लेकिन सड़क तैयार होने के बाद यह सफर एक दिन में ही पूरा हो जाएगा।

सबसे बड़ी बाधा पार : गर्बाधार से चीन सीमा लिपूलेख तक 75 किमी सड़क का निर्माण हो रहा है। इसमें सबसे दुर्गम माने जाने वाले मालपा तक सड़क तैयार कर सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने बड़ी बाधा पार कर ली है। असल में गर्बाधार से नजंग होते हुए मालपा तक सड़क निर्माण बीआरओ के लिए चुनौती था। 2006 में गर्बाधार से काम शुरू हुआ। मात्र नौ किमी सड़क तैयार करने में 14 साल लग गए। 2006 से 2017 तक पहाड़ काटकर मात्र तीन किमी सड़क बनाई जा सकी। काम में देरी होते देख 2017 में बीआरओ ने यह जिम्मा निजी कंपनी गर्ग एंड गर्ग को सौंप दिया था। यह प्रयोग सफल रहा। 2017 से अब तक 6.4 किमी सड़क तैयार हो गई। अब बस बीच में चार किमी की सड़क और तैयार करनी है।

अंतिम भारतीय पड़ाव तक आसान होगी आवाजाही : गर्बाधार- लिपूलेख मार्ग कैलास मानसरोवर यात्रियों के लिए विशेष लाभकारी होगा। बीआरओ का दावा है कि अक्टूबर से नवंबर तक गर्बाधार से अंतिम भारतीय पड़ाव नावीढांग तक सड़क तैयार कर ली जाएगी।

पिथौरागढ़ के मालपा में मंगलवार को तैयार सड़क का निरीक्षण करते सीमा सड़क संगठन व सेना के अधिकारी। साभार : सीमा सड़क संगठन

तो मालपा में बाधित नहीं होगी यात्रा

कैलास मानसरोवर यात्रा मालपा क्षेत्र में सर्वाधिक बाधित होती रही है। कठोर चट्टान वाले इस इलाके में अक्सर भूस्खलन होते रहते हैं। तीन वर्ष पहले यहां आई भीषण आपदा के कारण यात्रा को बीच में ही रोकना पड़ा था। बीते वर्ष भी भूस्खलन के कारण कैलास यात्रा करीब 15 दिनों तक बाधित रही। अब मालपा तक सड़क तैयार होने से यात्रा में आसानी होगी।

बीआरओ कमांडर मालपा पहुंचे

मालपा तक सड़क तैयार होने के बाद बीआरओ के कमांडर सोमेंद्र बनर्जी सैन्य अधिकारियों के साथ मंगलवार को मालपा पहुंचे। उन्होंने सड़क का निरीक्षण भी किया।

तबादला प्राथमिक अध्यापकों का अधिकार नहीं : हाई कोर्ट

- इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अध्यापकों की तबादला नीति में दखल से इन्कार

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की तबादला नीति के तहत महिला-पुरुष शिक्षकों या उनके परिवार के सदस्यों की गंभीर बीमारी की दशा में वरीयता देने को वैध करार दिया है। कोर्ट ने कहा, प्राथमिक अध्यापकों के तबादले के लिए दो दिसंबर 2019 को जारी नीति न तो संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ है न विरोधाभाषी। कोर्ट ने कहा, प्राथमिक अध्यापक को शहर से ग्रामीण या ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में तबादला कराने का अधिकार नहीं है।

न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी ने मनोज कुमार व 29 अन्य अध्यापकों की अर्जी खारिज करते हुए कहा, तबादला नीति में शर्तें लगाना प्रशासन का कार्य है जब तक वह मनमाना या संविधान विरोधी न हो तब तक कोर्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। याचिका में तबादला नीति के कालम 8(4) की वैधानिकता को चुनौती दी गई थी। जिसके तहत पांच क्वालिटी प्वाइंट देकर अध्यापिकाओं को वरीयता देने की व्यवस्था की गई है। कोर्ट ने कहा, महिलाओं को वरीयता देने से कानून का उल्लंघन नहीं होता है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट फाइल फोटो